

प्रेस विज्ञप्ति Press Release

आठवाँ बीमा मंथन, बीमा उद्योग के साथ आईआरडीएआई की तिमाही बैठक 11 और 12 नवंबर 2024 को हैदराबाद में आयोजित की गई।

यह संस्करण अपने ढंग का है जहाँ विनियमनकर्ता ने वैश्विक मानकों के साथ सुयोजित रहते हुए भविष्य के लिए तैयार होने के लिए उद्योग में गति बढ़ाने हेतु बीमा उद्योग के सर्वोच्च अधिकारियों के साथ प्रमुख विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया। यह मंथन इस तथ्य के कारण महत्व रखता है क्योंकि विनियमनकर्ता ने उद्योग के विभिन्न मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ भेंट की जिससे महत्वपूर्ण विषयों पर संकेन्द्रित पारस्परिक विचार-विमर्श किया जा सके। उद्योग का प्रतिनिधित्व मुख्य कार्यकारी अधिकारियों द्वारा उनके वित्त, प्रौद्योगिकी, अनुपालन, जोखिम और बीमांकिक कार्यों के प्रमुखों के साथ किया गया।

उद्योग की तैयारी, कार्यान्वयन की रणनीति, रोलआउट योजना, भारतीय जोखिम-आधारित पूँजी (आरबीसी) व्यवस्था, जोखिम-आधारित पर्यवेक्षी ढाँचा (आरबीएसएफ) और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानक (आईएफआरएस) अर्थात् इंड एस के अंगीकरण के मुख्य क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के अंगीकरण पर गहन विचार-विमर्श किया गया।

विनियमनकर्ता की टिप्पणियों पर विस्तृत पारस्परिक चर्चाएँ की गईं तथा बीमाकर्ताओं के अनुभव की साझेदारी आरबीसी को कार्यान्वित करने के लिए संचालित मात्रात्मक प्रभाव अध्ययन (क्यूआईएस) के निष्कर्षों, इंड एस के कार्यान्वयन और आरबीएस ढाँचे के अंतर्गत किये गये प्रायोगिक अध्ययन के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा किये गये अंतराल के निर्धारण पर केन्द्रित थी। आरबीसी क्यूआईएस। संबंधी टिप्पणियों की गहराई से समीक्षा की गई, इस बात पर विशेष फोकस के साथ कि जब अगला चरण प्रकट होता है तो बीमाकर्ता क्या प्रत्याशा कर सकते हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर एस के गहरे प्रभाव को स्वीकार करते हुए चर्चाएँ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अंतराल के निर्धारणों पर केन्द्रित रहीं। आरबीएसएफ प्रायोगिक अध्ययन से मुख्य अंतर्दृष्टियों पर चर्चा की गई, उद्योग की तैयारी पर और सफल कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कदमों पर प्रकाश डाला गया। ये पहलें केवल विनियामक उपाय नहीं हैं, परंतु इनकी बुनियाद पर बीमा उद्योग की भावी आघात-सहनीयता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का निर्माण किया जाएगा। चूँकि सभी बीमाकर्ता इन चिरस्थायी परिवर्तनों के लिए सामूहिक तौर पर तैयारी करेंगे, अतः सुदृढ़ अनुपालन, संवर्धित जोखिम प्रबंध, और अप्रतिम पारदर्शिता... इसके पूर्व कभी इनकी अत्यावश्यकता नहीं रही – संपूर्ण परिवर्तन को अपनाने और एक अधिकाधिक जटिल और गतिशील वैश्विक परिदृश्य में अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए यह उद्योग की निर्णायक पल है।

इस मंथन में बीमा सुगम भारत परिसंघ (बीएसआईएफ) की स्थिति पर एक महत्वपूर्ण अपडेट भी रहा, जिसने उद्योग को उत्साहित किया। जो कभी एक स्वप्नदर्शी संकल्पना थी, वह अब एक मूर्त वास्तविकता बन गई है। **बीमा सुगम**, जो एक डिजिटल सरकारी बुनियादी संरचना स्थापित करने का भारतीय बीमा क्षेत्र में एक ग्राहक-केन्द्रित नवोन्मेषण है, ने नागरिकों को बीमा क्षेत्र में आसानी से प्रवेश करने, लेनदेन करने और सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से उनके अपने समग्र बीमा अनुभव का संवर्धन करने का सामर्थ्य प्रदान करते हुए बीमा के परिदृश्य का कायापलट करने के लिए स्वयं को सधा हुआ रखा है। इसके सफल कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समूचे उद्योग से एक सामूहिक प्रतिबद्धता इसे एक नई आकृति प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है कि कैसे बीमाकर्ता बीमा व्यवसाय में पहुँच और पारदर्शिता का एक नया मानक स्थापित करते हुए उपभोक्ताओं के साथ परस्पर विचार-विमर्श (इंटरएक्शन) करते हैं।

ऐसे दौर में जहाँ डिजिटल रूपांतरण उद्योगों को एक नया आकार दे रहा है, वहीं साइबर सुरक्षा साइबर आशंकाओं में डरावनी वृद्धि के साथ एक सर्वोच्च चिंता के रूप में उभरी है। इन चर्चाओं के दौरान बीमाकर्ताओं ने आईटी प्रणालियों में असुरक्षितताओं, अन्य पक्ष विक्रेताओं, क्लाउड समाधानों की सुरक्षा, तथा कृत्रिम बुद्धि (एआई) द्वारा नियंत्रित साइबर आक्रमणों के छा रहे खतरों सहित, उद्योग जिन जोखिमों का सामना कर रहा है उनके संबंध में विचारों का आदान-प्रदान किया है। सूचना प्रणालियों (आईएस) सुरक्षा को मजबूत करने की अत्यावश्यकता पर संवाद हुआ है, जो विकसित हो रहे जोखिमों के विरुद्ध रक्षोपाय करने के लिए एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में उभरा है।

उक्त विचार-विमर्शों के दौरान प्रतिबिंबित अन्य क्षेत्रों में उद्योग का कार्यनिष्पादन, बीमा व्यापन में वृद्धि करने के लिए संकेन्द्रण के संभव क्षेत्र, पूँजी में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण अवसर, जैसे संशोधित विनियामक परिवेश में बीमाकर्ताओं की सूचीबद्धता शामिल हैं।

दो दिन के उक्त बीमा मंथन ने '2047 तक सबके लिए बीमा' की परिदृष्टि को साकार करने की दिशा में बीमा उद्योग की सामूहिक प्रतिबद्धता और संकल्प का प्रदर्शन किया।

The eighth Bima Manthan, the quarterly meeting of IRDAI with the insurance industry was held on 11th and 12th November 2024, in Hyderabad.

This edition is one of its kind where the Regulator had detailed deliberations with the top brass of the insurance industry on key issues to gear up industry to be future ready while also aligning with global standards. This Manthan garners importance because of the fact

that the Regulator met various Key Managerial Personnel of the Industry together, to have focused interaction on topics of importance. Industry was represented by the Chief Executive Officers along with their Chiefs of Finance, Technology, Compliance, Risk and Actuarial functions.

Discussions delved deep into the industry's readiness, implementation strategy, rollout plan, technology adoption in the key areas of Indian Risk-Based Capital (RBC) regime, Risk-Based Supervisory Framework (RBSF) and the adoption of International Financial Reporting Standards (IFRS) i.e. Ind AS.

There were detailed interactions on observations of the regulator and the experience sharing of the insurers on the findings of quantitative impact study (QIS) conducted to implement RBC, Gap assessment done by insurers as regards implementation of Ind AS and pilot studies carried out under RBS framework. The observations from the RBC QIS I were thoroughly reviewed, with a particular focus on what insurers can expect as the next phase unfolds. Recognizing the profound impact of Ind AS on financial reporting, discussions centred around gap assessments in critical areas. Key insights from the RBSF pilot study were discussed, shedding light on the industry's readiness and the steps required for successful implementation. These initiatives are not just regulatory shifts, but the very foundation upon which the future resilience and global competitiveness of the insurance industry will be built. As insurers collectively prepare for these monumental changes, the need for robust compliance, enhanced risk management, and unparalleled transparency has never been more urgent — this is the industry's defining moment to embrace transformation and safeguard its future in an increasingly complex and dynamic global landscape.

This Manthan also had an important update on the status of Bima Sugam India Federation (BSIF) which enthused the industry. What was once a visionary concept has now become a tangible reality. A customer-centric innovation in the Indian insurance sector of setting up the **BIMA SUGAM**, a digital public infrastructure, it is poised to revolutionize the insurance landscape, providing citizens with the ability to easily access, transact, and, most importantly, enhance their overall insurance experience. A collective commitment from the entire industry to ensure its successful implementation is set to reshape how insurers interact with consumers, setting a new standard of accessibility and transparency in the insurance business.

In an era where digital transformation is reshaping industries, cybersecurity has emerged as a paramount concern, with an alarming rise in cyber threats. Insurers, during these deliberations, exchanged views on the key risks facing the industry, including vulnerabilities in IT systems, third-party vendors, the security of cloud solutions, and the looming danger of AI-driven cyberattacks. There was dialogue on urgency of strengthening Information Systems (IS) security, which emerged as a critical theme to safeguard against evolving risks.

Other areas reflected upon during the interactions included performance of the Industry, possible areas of focus to enhance insurance penetration, important avenues for capital augmentation like listing of insurers in the revised regulatory environment.

The two day Bima Manthan showcased collective commitment and resolve of insurance industry towards achieving the vision of Insurance for All by 2047.
